

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

भारत-इंडोनेशिया का बड़ा आर्थिक दांव रुपये-रुपिया में होगा कारोबार, डॉलर पर निर्भरता घटाने की तैयारी

नई दिल्ली। और ने द्विपक्षीय व्यापार और भुगतान प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए स्थानीय मुद्राओं में लेनदेन तथा सीमा-पार क्यूआर भुगतान व्यवस्था को बढ़ावा देने पर सहमति जताई है।

इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और निवेश को सरल एवं कम लागत वाला बनाना है।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद भारतीय पर्यटक इंडोनेशिया में स्थानीय क्यूआर भुगतान प्रणाली के माध्यम से सीधे डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। वहीं दोनों देशों के कारोबारी भारतीय रुपये और इंडोनेशियाई रुपिया में व्यापारिक भुगतान कर सकेंगे, जिससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होने की संभावना है।

आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, स्थानीय मुद्रा में व्यापार होने से विदेशी मुद्रा विनिमय की लागत घटेगी, भुगतान प्रक्रिया तेज होगी और छोटे एवं मध्यम उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। इससे



आयात-निर्यात करने वाली कंपनियों, विद्यार्थियों, पर्यटकों और निवेशकों के लिए लेनदेन अधिक सुविधाजनक हो सकता है।

हालांकि विशेषज्ञ यह भी स्पष्ट करते हैं कि इसे अमेरिकी डॉलर की भूमिका समाप्त होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

वैश्विक व्यापार और विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की प्रमुख भूमिका बनी हुई है

यह समझौता मुख्य रूप से भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय लेनदेन को अधिक सरल, किफायती और लचीला बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

दोनों देशों के बीच

यह पहल क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को नई गति देने के साथ-साथ डिजिटल भुगतान और स्थानीय मुद्रा आधारित व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

राम मंदिर ट्रस्ट में मंथन या नई रणनीति?
चंपत राय से गोविंद देव गिरी की दो घंटे की मुलाकात ने बढ़ाई अटकलें



अयोध्या। राम मंदिर ट्रस्ट में हालिया बदलावों के बीच से मुलाकात की। चंपत राय के पद छोड़ने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात बताई जा रही है, जो लगभग दो घंटे तक चली। इस बैठक के बाद अयोध्या के धार्मिक और सामाजिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। हालांकि बैठक के एजेंडे या चर्चा के विषय पर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसे ट्रस्ट की भावी कार्ययोजना, प्रशासनिक व्यवस्था और मंदिर से जुड़े विभिन्न मुद्दों के संदर्भ में

महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राम मंदिर निर्माण और ट्रस्ट के कामकाज पर पूरे देश की निगाह रहती है। ऐसे में शीर्ष स्तर के पदधिकारियों की लंबी बैठक ने कई तरह के कयासों को जन्म दिया है। हालांकि, जब तक ट्रस्ट की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया जाता, तब तक बैठक के उद्देश्य या किसी निर्णय को लेकर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। अब सभी की नजर ट्रस्ट की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक बयान और भविष्य के निर्णयों पर टिकी है।

निज्जर हत्याकांड में अमेरिका की एंट्री
लॉरेंस-गोल्डी पर आरोप तय, भारत-कनाडा विवाद को मिल सकता है नया मोड़



नई दिल्ली। हत्या से जुड़े मामले में आरोप तय किए हैं। इस घटनाक्रम ने पहले से संवेदनशील भारत-कनाडा विवाद को नया अंतरराष्ट्रीय आयाम दे दिया है। निज्जर की जून 2023 में के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इसके बाद तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री ने भारतीय एजेंसियों की संभावित भूमिका का सार्वजनिक रूप

से आरोप लगाया था। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें “बेतुका और दुर्भावनापूर्ण” बताया था। अमेरिकी कार्रवाई से संकेत मिलता है कि जांच अब केवल कनाडा तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी कथित आपराधिक नेटवर्क और उनकी गतिविधियों की पड़ताल कर रही हैं। हालांकि, आरोप तय होना दोष सिद्ध होने के समान नहीं है और अंतिम

निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा। यह मामला केवल एक हत्या की जांच नहीं रह गया है। इसके प्रभाव भारत-कनाडा संबंधों, खालिस्तानी गतिविधियों, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग और संगठित अपराध के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई तक फैल चुके हैं। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्य और आगे की जांच इस मामले को किस दिशा में ले जाती है।

पैरामीटर्स में प्रगति लाएं और पैरामीटर्स सैचुरेशन लाने हेतु बनाएं कार्य योजना-जिला पंचायत सीईओ

नवल किशोर

कटनी। सभी पैरामीटर्स में प्रगति लाएं एवं सैचुरेशन हेतु आवश्यक कार्य योजना तैयार किया जाना सुनिश्चित करें। इस आशय के निर्देश जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने बुधवार को जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, किसान कल्याण तथा कृषि, पशुपालन एवं अन्य विभागों के अधिकारियों को दिए। अवगत होवे कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा संचालित आकांक्षी विकासखंड रीटी हेतु विभिन्न संकेतकों की प्रगति हेतु जिला पंचायत सीईओ की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। सुश्री कौर ने स्वास्थ्य विभाग से गर्भावस्था के दौरान देखभाल, सुरक्षित प्रसव और गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, कुपोषण निवारण एवं पोषण वितरण, आंगनबाड़ी भवनों में कार्यात्मक शौचालय, पेयजल सुविधा, शिक्षा विभाग से स्कूल छोड़ने की दर में कमी और सुविधाएं, कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम, कृषि एवं पशुपालन विभाग से ग्रामीण आजीविका एवं मृदा स्वास्थ्य, गठित किसान उत्पादक संगठन, गोवंश पशु

आकांक्षी विकासखंड रीटी के शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों के पैरामीटर्स की प्रगति की सुश्री कौर ने गहन समीक्षा कर दिए निर्देश

टीकाकरण, डिजिटल और भौतिक कनेक्टिविटी, जल जीवन मिशन नल कनेक्शन से प्रत्येक घर में पीने योग्य पानी, ग्राम पंचायत में सक्रिय इंटरनेट और वाई-फाई सुविधा, सामाजिक और डिजिटल सशक्तिकरण आदि पैरामीटर्स पर बिंदुवार विस्तार से जानकारी लेते हुए प्रगति की समीक्षा की एवं सुझाव साझा करते हुए प्रगति में आने वाली समस्याओं से रूबरू हुई। उन्होंने कमजोर संकेतकों पर ध्यान देकर विभिन्न विभागों को समन्वय से सुधारात्मक कार्य योजना तैयार कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

इनकी रही मौजूदगी

समीक्षा बैठक में डॉ राज सिंह ठाकुर, यशवंत वर्मा, प्रेम नारायण तिवारी, राजेश अग्रहरि, वन श्री कुवैती, राजेश नरेंद्र सिंह, अभिराज दुबे सहित अन्य जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी रही।



वार्ड क्रमांक 29 में डिप्टी कमिशनर प्रतीक रावजी एवं उनके साथ नगर निगम के अधिकारियों को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया, जैसे रोड़ों पर एवं कॉलोनी में जल भराव, सीवर चौक खराब रोड़ों से एवं पार्कों के मरम्मत कार्य डिप्टी कमिशनर महोदय वार्ड में समस्याएं देखी एवं उनके निराकरण हेतु नगर निगम अधिकारियों के दिशा निर्देश दिए।



कपिलधारा योजना में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़, 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते सरपंच और सरपंच पति लोकायुक्त के हथे चढ़े

अतुल जैन

(कुएं के भुगतान के एवज में मांगी थी घूस, ग्वालियर लोकायुक्त की ट्रेप कार्रवाई से खनियाधाना में मचा हड़कंप)

खनियाधाना। शिवपुरी जिले के खनियाधाना जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत जुंगीपुर में बुधवार को ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत की सरपंच केशवती कोली और उनके पति खेमचंद कोली को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी कपिलधारा योजना के तहत बनाए गए कुएं के निर्माण का भुगतान जारी कराने के बदले हितग्राही से रिश्वत की मांग की थी। लोकायुक्त की इस कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया।

(भुगतान रोककर बनाई रिश्वत की शर्त)

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत जुंगीपुर निवासी राहुल सिंह यादव ने वर्ष 2025 में कपिलधारा योजना के अंतर्गत अपने खेत पर कुएं का निर्माण कराया था। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उन्होंने योजना के तहत मिलने वाली राशि के भुगतान के लिए पंचायत में आवश्यक प्रक्रिया पूरी की। आरोप है कि भुगतान स्वीकृत करने के बजाय सरपंच केशवती कोली और उनके पति खेमचंद कोली ने 20 हजार रुपये की रिश्वत की मांग कर दी। बिना रिश्वत दिए भुगतान नहीं होने की बात कहे जाने पर हितग्राही मानसिक रूप से परेशान हो गया।

(लोकायुक्त से की शिकायत, शुरू हुआ गोपनीय सत्यापन)

रिश्वत की मांग से परेशान राहुल सिंह यादव ने 3 जुलाई 2026 को ग्वालियर स्थित लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त अधिकारियों ने पूरे मामले का गोपनीय सत्यापन कराया। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ट्रेप कार्रवाई की योजना तैयार की गई।

(बुधवार सुबह बिछाया जाल, रिश्वत लेते ही दबोच लिया)

पूर्व निर्धारित योजना के तहत बुधवार सुबह करीब 10 बजे फरियादी 20



हजार रुपये की रिश्वत की राशि लेकर सरपंच के निवास, जो खनियाधाना में उपजेल के पीछे स्थित है, पहुंचा। जैसे ही सरपंच केशवती कोली और उनके पति खेमचंद कोली ने फरियादी से रिश्वत की राशि स्वीकार की, पहले से आसपास मौजूद लोकायुक्त टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। रिश्वत की राशि भी मौके से बरामद कर ली गई।

(कार्रवाई के बाद फैली अफवाहें, दिनारा रेस्ट हाउस में पूरी हुई कानूनी प्रक्रिया)

लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद खनियाधाना कस्बे में कुछ ही मिनटों में खबर फैल गई। हालांकि टीम आरोपियों और फरियादी को तत्काल अपने साथ लेकर रवाना हो गई, जिससे करीब तीन घंटे तक किसी को यह जानकारी नहीं मिल सकी कि कार्रवाई करने वाली टीम आरोपियों को कहां लेकर गई है। इस दौरान कस्बे में यह अफवाह भी फैल गई कि कार्रवाई करने वाली टीम फर्जी थी। बाद में जानकारी मिली कि लोकायुक्त की टीम आरोपियों को लेकर पिछोर थाना क्षेत्र से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित दिनारा रेस्ट हाउस पहुंची, जहां पंचनामा, दस्तावेजी कार्रवाई और अन्य वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी की गईं।

(अनुभवी अधिकारियों ने संभाली कार्रवाई की कमान)

पूरे ट्रेप ऑपरेशन का नेतृत्व लोकायुक्त निरीक्षक उपेंद्र दुबे एवं निरीक्षक अंजली शर्मा ने किया। टीम में प्रधान आरक्षक देवेन्द्र पवैया, हेमंत शर्मा, आरक्षक प्रशांत कुशवाहा, अंकेश शर्मा, सुरेंद्र सेमल, आरिफ खान, बिसंबर भदौरिया, बलबीर सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे। पूरी कार्रवाई विधिवत पंचों की मौजूदगी में संपन्न कराई गई।

(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज)

लोकायुक्त पुलिस ने सरपंच केशवती कोली एवं उनके पति खेमचंद

कोली के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। यदि जांच में अन्य तथ्य सामने आते हैं तो उनसे जुड़े व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी।

(सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार पर बड़ा सवाल)

कपिलधारा योजना किसानों और ग्रामीण हितग्राहियों के लिए चलाई जाने वाली महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना है। ऐसे में योजना का लाभ दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने का मामला सामने आने से पंचायत व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह सख्ती से कार्रवाई होती रही तो सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगेगा।

(इनका कहना है)

“वर्ष 2025 में ग्राम पंचायत झुन्नीपुरा निवासी राहुल सिंह यादव ने ‘कपिलधारा’ योजना के तहत कुएं का निर्माण कराया था। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद सामग्री भुगतान संबंधी बिल पर हस्ताक्षर कराने के एवज में ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती केशवती कोली एवं उनके पति खेमचंद कोली द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता ने 3 जुलाई 2026 को लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसके सत्यापन में रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद 8 जुलाई 2026 को लोकायुक्त टीम ने ट्रेप कार्रवाई करते हुए सरपंच एवं उनके पति को शिकायतकर्ता से 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इस प्रकरण में ग्राम पंचायत सचिव की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई है। ट्रेप कार्रवाई पहले पिंपरोल में प्रस्तावित थी, लेकिन सर्किट हाउस उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे दिनारा में संपन्न किया गया।”

(उपेंद्र दुबे, लोकायुक्त निरीक्षक)

चालान में अक्ल, ट्रैफिक संभालने में फिसड़ी! ट्रैफिक पुलिस चौराहों से गायब, जाम में फंसा इंदौर, जनता बेहाल

इंदौर। शहर का ट्रैफिक सिस्टम इन दिनों पूरी तरह भगवान भरोसे नजर आ रहा है। पाटनीपुरा, विजय नगर, एमवाय, जवाहर मार्ग, लालगंज चौराहा, वर्ल्ड कप चौराहा और बंगाली चौराहा समेत दर्जनों प्रमुख मार्गों पर वाहन घंटों रेंग रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाली पुलिस कहीं दिखाई नहीं दे रही। सवाल यह है कि जब शहर जाम से कराह रहा है तो ट्रैफिक पुलिस आखिर है कहाँ? शहर में एक तरफ फ्लाईओवर और ब्रिज निर्माण के नाम पर सड़कों को संकरा कर दिया गया है, दूसरी तरफ सर्विस रोड की बहाली और बारिश के कारण बने गड्ढों ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। नतीजा यह है कि हर प्रमुख



चौराहा सुबह से रात तक जाम का अड्डा बन चुका है। लोग कार्यालय, स्कूल और अस्पताल पहुंचने में परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार विभागों को इससे कोई फर्क

पड़ता नहीं दिख रहा।

सबसे बड़ा सवाल ट्रैफिक पुलिस की कार्यशैली पर खड़ा हो रहा है। आम दिनों में हेलमेट, सीट बेल्ट और दस्तावेज जांच के लिए हर चौराहे पर तैनात रहने वाली पुलिस जाम के समय अचानक गायब क्यों हो जाती है? यदि पुलिस की मौजूदगी से वीआईपी मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक सुचारू हो सकता है तो आम जनता के लिए वही व्यवस्था क्यों नहीं दिखाई देती? करोड़ों रुपए के चालान काटने का दावा करने वाला ट्रैफिक अमला शहरवासियों को जाम से राहत दिलाने में नाकाम साबित हो रहा है। चौराहों पर सिग्नलों की टाइमिंग भी वर्षों पुरानी व्यवस्था के अनुसार चल रही है।

कुछ वाहन आगे बढ़ते हैं और सिग्नल फिर लाल हो जाता है, जिससे लंबी कतारें लग जाती हैं। इसके बावजूद सुधार की कोई गंभीर कोशिश नजर नहीं आती। शहर की जनता पूछ रही है कि ट्रैफिक पुलिस का काम केवल चालान बनाना है या यातायात को सुचारू रखना भी? यदि जाम के समय चौराहों पर पुलिसकर्मी मौजूद रहें, सिग्नलों की टाइमिंग सुधारी जाए और निर्माण एजेंसियों को समयबद्ध काम पूरा करने के लिए बाध्य किया जाए तो स्थिति काफी हद तक संभल सकती है। फिलहाल तो इंदौर की सड़कें यही कह रही हैं कि व्यवस्था सो रही है और जनता रोजाना जाम की सजा भुगत रही है।

जिलाबदर कुख्यात बदमाश इमरान उर्फ इम्मु अवैध कट्टे के साथ गिरफ्तार

चंदन नगर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, देशी कट्टा व जिंदा कारतूस जब्त, आर्म्स एक्ट और राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज

खुशबू श्रीवास्तव

इंदौर। चंदन नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिलाबदर कुख्यात बदमाश इमरान उर्फ इम्मु उर्फ निजाम को अवैध देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, मादक पदार्थ, बलवा, जुआ-सट्टा सहित करीब चार दर्जन आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार, पुलिस आयुक्त के निर्देश पर गुंडे-बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिलाबदर बदमाश चंदन नगर क्षेत्र में अवैध हथियार के साथ घूम रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी तिलक कारोले के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 10 हजार रुपये बताई गई है। पूछताछ में आरोपी



हथियार रखने का कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका।

जांच में सामने आया कि पुलिस आयुक्त के आदेश पर आरोपी को एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया गया था, लेकिन आदेश का उल्लंघन कर वह प्रतिबंधित क्षेत्र इंदौर शहर में पाया गया। इस पर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 तथा मध्यप्रदेश



राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी इमरान उर्फ इम्मु उर्फ निजाम के खिलाफ हत्या

के प्रयास, मारपीट, अड़ीबाजी, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, आर्म्स एक्ट, अवैध मादक पदार्थ, अवैध हथियार, जुआ और सट्टा एक्ट सहित करीब चार दर्जन आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

सराहनीय भूमिका

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी तिलक कारोले, उपनिरीक्षक सौरभ कुशवाहा, सहायक उपनिरीक्षक भगवान सिंह सिसोदिया, प्रधान आरक्षक जितेंद्र सोलंकी तथा आरक्षक धीरज पांडेय, हरि सिंह राजपूत, अनिल मकवाना, सुनील सोनी एवं अरुण जाट की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

इंदौर में साफ पेयजल का संकट : सैकड़ों परिवार गंदा और मटमैला पानी पीने को मजबूर, निगम ने शुरू कराया सर्वे

इंदौर। शहर में इस मानसून अब तक करीब 13 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है, जिससे अधिकांश बोरेल और भूजल स्रोत रिचार्ज हो गए हैं। इसके बावजूद पुराने शहर के कई इलाकों के लोग आज भी स्वच्छ पेयजल के लिए परेशान हैं। सदर बाजार, मराठी मोहल्ला, जूना रिसाला, गली नंबर 1, 2, 3,



4 और अहिल्या पलटन सहित कई क्षेत्रों में लोगों को गंदा और मटमैला पानी मिल रहा है, जिससे सैकड़ों परिवार पानी उबालकर पीने को मजबूर हैं। समस्या की गंभीरता को देखते हुए

नगर निगम ने एक एनजीओ के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे शुरू कराया है। सर्वे टीम घर-घर जाकर जलापूर्ति व्यवस्था, पेयजल की गुणवत्ता और पाइपलाइन की स्थिति की जानकारी जुटा रही है। विशेष रूप से उन इलाकों का निरीक्षण किया जा रहा है, जहां पेयजल और ड्रेनेज लाइनें एक-दूसरे के बेहद करीब बिछी हुई हैं।

पुरानी पाइपलाइन और ड्रेनेज नेटवर्क बन रहे वजह - नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, पुराने शहर के कई हिस्सों में ड्रेनेज व्यवस्था बैकलेन से संचालित होती है। कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त या जर्जर पाइपलाइन के कारण ड्रेनेज अथवा हौज का दूषित पानी पेयजल लाइन में प्रवेश कर जाता है। यह पानी पाइपलाइन में जमा रहता है और अगले दिन जलापूर्ति शुरू होने पर लोगों के घरों तक पहुंच जाता है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि वे कई दिनों से गंदा पानी मिलने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। लोगों ने निगम से दूषित पाइपलाइन बदलने और जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार की मांग की है।

पुणे में बारिश बनी आफत: कूड़े का पहाड़ इमारत पर गिरा, भवन ढहा; 16 लोगों के दबे होने की आशंका

Pune। महाराष्ट्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब जानलेवा साबित होने लगी है। राज्य के कई जिलों में भारी वर्षा के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। इसी बीच बुधवार को पुणे से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई, जहां बारिश के बीच कूड़े का विशाल ढेर अचानक खिसककर एक रिहायशी इमारत पर आ गिरा। मलबे के भारी दबाव से इमारत देखते ही देखते ढह गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस हादसे में करीब 16 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई

जा रही है।

घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस, दमकल विभाग और आपदा राहत दल मौके पर पहुंच गए। बचावकर्मी जेसीबी मशीनों और अन्य उपकरणों की मदद से मलबा हटाकर लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटे हैं। राहत कार्य युद्धस्तर पर जारी है और मलबे में फंसे लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचने का प्रयास

किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, बचाव अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, इसके लिए सभी संबंधित एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, लगातार हो रही तेज बारिश के कारण कूड़े के पहाड़ की मिट्टी और कचरा ढीला पड़ गया था। अचानक पूरा ढेर खिसककर पास स्थित इमारत पर आ गिरा, जिससे भवन की संरचना पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कुछ ही क्षणों में वह भरभराकर ढह गया।

हादसे के समय इमारत में कई परिवार मौजूद थे, जिससे लोगों के मलबे में दबने की आशंका और बढ़ गई है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। निचले इलाकों में जलभराव, सड़कें बंद होने और यातायात प्रभावित होने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

उच्चतर विकसित अस्तित्व का निर्माण करता है सहजयोग



सहजयोग ध्यान से व्यक्ति के व्यक्तित्व में किस प्रकार परिवर्तन आता है इसका वर्णन श्री माताजी निर्मला देवी जी ने अपनी अमृतवाणी में इस प्रकार किया है, सहजयोग एक ऐसी अभिनव चीज है, जो आपकी वास्तविकता को आपके अंदर स्थापित करता है, जिसके कारण आप सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी वास्तविकता ही बहुत सुन्दर है। यह आनंददायक है, और तब आप इससे दूर भागना नहीं चाहते। यही वो बात है जिसे हमें समझना है, कि हम यहाँ अपनी वास्तविकता को पाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए आए हैं।

अपने आप को जानने से, कितनी चीजें हमारे साथ घटित हो सकती हैं? आपको शायद इसका अनुमान नहीं है। यह पूरी संपदा जो आप हैं, पूरा वैभव जो आप हैं, पूरी सुंदरता जो आप हैं, यह सब आपकी अपनी हो जाती है। आप अपने जीवन के स्वामी बन जाते हैं.....आप एक अलग तरह के व्यक्ति बन जाते हैं। आप एक उच्चतर विकसित जीवात्मा बन जाते हैं। और तब आप महसूस करते हैं कि आप

अचानक एक ऐसे अस्तित्व बन गए हैं, जो सामूहिक रूप से जागृत है। (२४ नवंबर १९८०) अपनी उपस्थिति से, आप दूसरों को परिवर्तित करना आरंभ कर देते हैं। अपने अस्तित्व से आप दूसरे लोगों को बदलना शुरू करते हैं। आप वातावरण को, और नकारात्मकता की सूक्ष्म समस्याओं को परिवर्तित करने लगते हैं। यह सब उस पेड़ की तरह से कार्यान्वित होता है, जिस तरह से एक वृक्ष फलता-फूलता है। बहार की यह सुगंध अपने चारों ओर एक अलग तरह का आभामंडल बनाती है, जिससे यह अपने आस पास की सभी मधुमक्खियों को शहद इकट्ठा करने के लिए आकर्षित करती है। इसी तरह, जब एक व्यक्ति आत्मसाक्षात्कारी बनता है, आलोकित होता है, उसका आभामंडल निखर उठता है, और वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देता है। (१६ नवंबर १९८०) आत्मसाक्षात्कार को प्राप्त करने हेतु अपने नजदीकी सहजयोग ध्यान केंद्र की जानकारी टोल फ्री नंबर 1800 2700 800 से प्राप्त कर सकते हैं या वेबसाइट www.sahajayoga.org.in पर देख सकते हैं। सहज योग पूर्णतया निशुल्क है।

करैरा बाजार में शराब पीकर दौड़ा रहा था 12 लाख की अर्टिगा, पुलिस ने किया जब्त; न्यायालय ने ठोका 11 हजार का जुर्माना

तेज रफ्तार और खतरनाक ड्राइविंग पर करैरा पुलिस की सख्त कार्रवाई, एमवी एक्ट की धाराओं 183, 184 व 185 के तहत चालान

हेमंत भार्गव

करैरा। शिवपुरी जिले के करैरा थाना पुलिस ने बाजार क्षेत्र में शराब के नशे में तेज गति एवं खतरनाक ढंग से मारुति अर्टिगा कार चलाने वाले चालक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 12 लाख रुपये कीमत की कार क्रमांक MP07 AE 6398 जब्त कर ली। चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183, 184 एवं 185 के तहत चालान प्रस्तुत किया गया, जिस पर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) करैरा श्री भूपेंद्र यादव ने 11,000 का जुर्माना लगाया।



पुलिस अधीक्षक यांगचेन भूटिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजीव मुले एवं प्रभारी एसडीओपी प्रशांत शर्मा के निर्देशन तथा थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह छाबई के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।

पुलिस के अनुसार, चालक जयवीर चौरसिया, निवासी नरवर (जिला शिवपुरी), करैरा बाजार में शराब के नशे में तेज रफ्तार एवं लापरवाही से कार चला रहा था। बाजार क्षेत्र में भीड़भाड़ को देखते हुए समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो कोई गंभीर सड़क दुर्घटना हो सकती थी। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह छाबई, उपनिरीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक मोहन बघेल, आरक्षक हरेंद्र गुर्जर, मत्स्येंद्र गुर्जर, राधेश्याम जादौन, शिवम यादव एवं रामनिवास गुर्जर की सराहनीय भूमिका रही।

एमईएस कालोनी में सूने मकान में 4-5 लाख की चोरी पुलिस के लिए बनी चुनौती



नवल किशोर

कटनी। माधवनगर अंतर्गत एमईएस कालोनी में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यहाँ एक कास्मेटिक कारोबारी के सूने मकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने करीब 4-5 लाख रुपये की चोरी की घटना को अंजाम दिया। वारदात के बाद से क्षेत्र के व्यापारियों और नागरिकों में सुरक्षा को लेकर चिंता देखी जा रही है।

घर का ताला तोड़कर भीतर घुसे चोर

यह वारदात 6 और 7 जुलाई की दरम्यानी रात की बताई जा रही है। मकान मालिक और कास्मेटिक कारोबारी अनिल कलवानी अपने परिवार (पत्नी और बच्चों) के साथ घर पर ताला लगाकर ससुराल गए हुए थे। मकान को सूना पाकर अज्ञात चोरों ने दाखिल होकर भीतर रखी आलमारी का ताला तोड़ दिया। कारोबारी के अनुसार, चोर आलमारी में रखे:

1,95,000 नगद

सोने की चेन और लॉकेट

सोने-चांदी के कान के बाले व अन्य कीमती जेवरात लेकर चंपत हो गए। जब पीड़ित परिवार ससुराल से वापस लौटा, तब घर के बिखरे हुए सामान और टूटे ताले को देखकर चोरी की इस बड़ी वारदात का खुलासा हुआ।

करैरा पुलिस का अवैध शराब कारोबार पर प्रहार, 60 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब सहित आदतन तस्कर गिरफ्तार



महुअर नदी पुल के पास कार्रवाई, आरोपी को न्यायालय में पेश कर भेजा गया उप जेल करैरा

हेमंत भार्गव

करैरा पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब के साथ एक आदतन आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लगभग 6,000 मूल्य की अवैध शराब जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक यांगचेन भूटिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं प्रभारी एसडीओपी करैरा प्रशांत शर्मा के निर्देशन तथा थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह छाबई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गणेश मंदिर, महुअर नदी पुल के पास सड़क किनारे दबिशा दी। कार्रवाई के दौरान आरोपी सद्दाम खान, निवासी बगीचा सरकार मंदिर के

पास, करैरा, को अवैध शराब बेचने के उद्देश्य से ले जाते हुए पकड़ा गया।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 30-30 लीटर की नीले रंग की दो प्लास्टिक की कट्टियों में कुल 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब जब्त की। आरोपी के विरुद्ध थाना करैरा में अपराध क्रमांक 457/26 के तहत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार सद्दाम खान अवैध शराब बिक्री का आदतन अपराधी है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे उप जेल करैरा भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह छाबई, सउनि शैलेन्द्र सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक राजेंद्र यादव तथा आरक्षक हरेंद्र गुर्जर, मत्स्येंद्र गुर्जर, राधेश्याम जादौन, विकास दुबे, मधुर श्रीवास्तव, धर्मवीर रावत एवं महेश मांझी की सराहनीय भूमिका रही।

महिला कांग्रेस ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की सीबीआई जांच मांग ट्रस्ट को RTI के दायरे में लाने की भी मांग, कहा निष्पक्ष जांच से ही सामने आएगा पूरा सच

नवल किशोर

कटनी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाई गई दान की राशि चोरी के मामले को लेकर महिला कांग्रेस ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिला कांग्रेस मध्यप्रदेश की प्रदेश महासचिव सौम्या राँधेलिया के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कटनी सीएसपी को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की CBI से निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराने की मांग की। ज्ञापन प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, CBI निदेशक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा उत्तर प्रदेश एवं मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशकों के नाम प्रेषित किया गया। महिला कांग्रेस ने ज्ञापन में कहा कि श्रीराम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और चढ़ावे की राशि में कथित गड़बड़ी एवं चोरी की घटनाओं ने देशभर के लोगों के विश्वास को ठेस पहुंची है। ऐसे संवेदनशील मामले की जांच किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आए और दोषियों के खिलाफ



निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई हो सके।

ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि मंदिर के दान-पात्र, लेखा-जोखा, सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए तथा वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई जाए। साथ ही मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन और दान राशि के उपयोग

में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ट्रस्ट को सूचना का अधिकार (RTI) के दायरे में लाने की मांग भी उठाई गई। महिला कांग्रेस ने यह भी कहा कि वर्तमान में सरकार द्वारा एसआईटी गठित कर कुछ लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए हैं, लेकिन अब तक कथित चोरी के मास्टरमाइंड का

खुलासा नहीं हो सका है। संगठन ने आरोप लगाया कि मामले के मुख्य आरोपियों तक जांच नहीं पहुंची है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

प्रदेश महासचिव सौम्या राँधेलिया ने कहा कि महिला कांग्रेस का उद्देश्य किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच के माध्यम से सत्य को सामने लाना है। यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देशभर में महिला कांग्रेस इस मामले में CBI जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है, ताकि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास सुरक्षित रह सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान महिला कांग्रेस की मीनाक्षी वल्लवी, हेमा शर्मा, माया चौधरी, नीरा सोनी, मनीषा सिंह एवं सौम्या परमार सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहें। श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक ओर SIT जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही हैं, वहीं विपक्ष इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग कर है।

बामौरकलां के सीताराम यादव बने मध्यप्रदेश पुलिस सब-इंस्पेक्टर, पहले ही प्रयास में हासिल की सफलता

अतुल जैन

ग्रामीण विद्यालयों से पढ़ाई कर रचा इतिहास, परिवार में अब दो-दो सब-इंस्पेक्टर; युवाओं के लिए बने प्रेरणा

खनियांधाना। सीमित संसाधनों और ग्रामीण परिवेश में शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत निरंतर की जाए, तो सफलता निश्चित रूप से कदम चूमती है। इस बात को बामौरकलां क्षेत्र के होनहार युवा सीताराम यादव ने सच साबित कर दिखाया है। उन्होंने मध्यप्रदेश पुलिस सब-इंस्पेक्टर (एमपी पुलिस एसआई) भर्ती परीक्षा में पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे बामौरकलां क्षेत्र का नाम प्रदेशभर में गौरवान्वित किया है। उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र में हर्ष का माहौल है और लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। सीताराम यादव की प्रारंभिक शिक्षा से लेकर कक्षा 12वीं तक की पूरी स्कूली पढ़ाई बामौरकलां के विद्यालयों में हुई। इसके बाद उन्होंने इंदौर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। ग्रामीण क्षेत्र में रहकर कठिन परिस्थितियों के बीच अध्ययन करते हुए उन्होंने नए परीक्षा पैटर्न, संशोधित पाठ्यक्रम और बदले हुए शारीरिक मापदंडों के अनुरूप तैयारी की तथा पहले ही प्रयास में सब-इंस्पेक्टर परीक्षा उत्तीर्ण कर अपनी प्रतिभा और लगन का परिचय दिया।

सीताराम यादव की यह सफलता उनकी पहली उपलब्धि नहीं है। इससे पहले भी वे कई प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित हो चुके हैं। उनका



चयन दो बार मध्यप्रदेश पुलिस, पटवारी, जेल विभाग, सीआईएसएफ, रेलवे तथा मध्यप्रदेश वन विभाग जैसी विभिन्न सेवाओं में हो चुका है। अब मध्यप्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर पद पर चयन ने उनकी उपलब्धियों में एक और गौरवपूर्ण अध्याय जोड़ दिया है। उनकी लगातार मिल रही सफलताएं अनुशासित तैयारी, आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम का परिणाम मानी जा रही हैं। इस उपलब्धि ने परिवार को भी विशेष पहचान दिलाई है। सीताराम यादव के बड़े भाई नीलम सिंह यादव, बहादुरपुर (जिला अशोकनगर), पहले से ही मध्यप्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। अब सीताराम के चयन के बाद परिवार में दो-दो सब-इंस्पेक्टर हो गए हैं, जो पूरे क्षेत्र के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। सीताराम यादव की सफलता इस बात का जीवंत उदाहरण है कि संसाधनों की कमी कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बनती, यदि व्यक्ति का संकल्प मजबूत हो और तैयारी ईमानदारी से की जाए। बामौरकलां के लोगों का मानना है कि सीताराम यादव की यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का मजबूत संदेश है। गांव की पाठशाला से निकलकर प्रदेश की प्रतिष्ठित सेवा में चयनित होना यह साबित करता है कि प्रतिभा किसी बड़े शहर की मोहताज नहीं होती। उनकी सफलता ने पूरे क्षेत्र के युवाओं में नई ऊर्जा और बड़े सपने देखने का आत्मविश्वास जगाया है।

पुलिस मुख्यालय भोपाल के सेफ विलक 2.0 सायबर सुरक्षा अभियान के समापन पर कटनी पुलिस के CEIR PORTAL के माध्यम से 110 गुम मोबाइलों को खोजने में प्राप्त की सफलता

मोबाइल पाकर मोबाइल धारकों के खिले चेहरे। कटनी पुलिस को दिया धन्यवाद एवं सायबर अपराधों से दूर रहने एवं सायबर जागरूकता फैलाने की लिए शपथ

नवल किशोर

कटनी। जिले के विभिन्न थाना अंतर्गत रहने वाले नागरिकों के मोबाइल किसी न किसी कारण से कहीं गुम हो गये या गिर गये हैं, आजकल यह एक आम समस्या बनती जा रही है। ऐसे पीड़ित



मोबाइल धारकों द्वारा कटनी सायबर सेल एवं भारत सरकार के CEIR PORTAL में गुम मोबाइल खोजने हेतु आवेदन पत्र दिये गये थे। जिस पर से पुलिस अधीक्षक कटनी अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन में एवं अति. पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य के मार्गदर्शन में जिले में गुम हुये मोबाइलों की शिकायतों में त्वरित कार्यवाही करने व गुम मोबाइलों को सर्च करने के

निर्देश सायबर सेल कटनी को मिले थे, कार्यालय सायबर सेल द्वारा गुम मोबाइलों के आवेदनो में जिला कटनी तथा अन्य जिलों के संबंधित थाने की मदद से कुल 110 नग मोबाइल कीमत लगभग 20,00,000/- (बीस लाख रुपये) के बरामद कर पुलिस मुख्यालय भोपाल के सेफ विलक 2.0 सायबर सुरक्षा अभियान के समापन के अवसर पर विभिन्न आवेदकों को उनके गुम हुए मोबाइल फोन पुलिस अधीक्षक कटनी द्वारा लौटाये गये।

इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा द्वारा आमजन से गुम मोबाइल के संबंध में भारत सरकार के CEIR PORTAL में त्वरित रूप से आवेदन कर आईएमईआई को ब्लॉक करने की अपील की है। इस पोर्टल के माध्यम से आमजन भी सीधे शिकायत दर्ज कर सकते एवं शिकायत की अद्यतन स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। इससे आमजन के समय की बचत होगी एवं पुलिस तथा जनता के मध्य परीक्षा रहती है। उपरोक्त मोबाइल अधिकतर साप्ताहिक बाजार में लापरवाही से गिरने, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में भूलने एवं आवागमन के समय जेब से गिरने से गुम हुए थे। साइबर टीम द्वारा पुलिस अधीक्षक कटनी के निर्देशन में लगातार सर्चिंग की जा रही थी जिसके परिणामस्वरूप गुम मोबाइल प्रदेश के विभिन्न जिलों के सायबर सेल एवं पुलिस थानों की मदद से प्राप्त किये गये हैं। उपरोक्त मोबाइल खोजने में सायबर सेल टीम कटनी एवं संबंधित थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पैरामीटर्स में प्रगति लाएं और पैरामीटर्स सैचुरेशन लाने हेतु बनाएं कार्य योजना- जिला पंचायत सीईओ



आकांक्षी विकासखंड रीटी के शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों के पैरामीटर्स की प्रगति की सुश्री कौर ने गहन समीक्षा कर दिए निर्देश

नवल किशोर

कटनी । सभी पैरामीटर्स में प्रगति लाएं एवं सैचुरेशन हेतु आवश्यक कार्य योजना तैयार किया जाना सुनिश्चित करें। इस आशय के निर्देश जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने बुधवार को जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, किसान कल्याण तथा कृषि, पशुपालन एवं अन्य विभागों के अधिकारियों को दिए। अवगत होवें कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा संचालित आकांक्षी विकासखंड रीटी हेतु विभिन्न संकेतकों की प्रगति हेतु जिला पंचायत सीईओ की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। सुश्री कौर ने स्वास्थ्य विभाग से गर्भावस्था के दौरान देखभाल, सुरक्षित प्रसव और गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, कुपोषण निवारण एवं पोषण वितरण, आंगनवाड़ी भवनों में कार्यात्मक शौचालय, पेयजल सुविधा, शिक्षा विभाग से

स्कूल छोड़ने की दर में कमी और सुविधाएं, कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम, कृषि एवं पशुपालन विभाग से ग्रामीण आजीविका एवं मुदा स्वास्थ्य, गठित किसान उत्पादक संगठन, गोवंश पशु टीकाकरण, डिजिटल और भौतिक कनेक्टिविटी, जल जीवन मिशन नल कनेक्शन से प्रत्येक घर में पीने योग्य पानी, ग्राम पंचायत में सक्रिय इंटरनेट और वाई-फाई सुविधा, सामाजिक और डिजिटल सशक्तिकरण आदि पैरामीटर्स पर बिंदुवार विस्तार से जानकारी लेते हुए प्रगति की समीक्षा की एवं सुझाव साझा करते हुए प्रगति में आने वाली समस्याओं से रूबरू हुई। उन्होंने कमजोर संकेतकों पर ध्यान देकर विभिन्न विभागों को समन्वय से सुधारात्मक कार्य योजना तैयार कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

इनकी रही मौजूदगी

समीक्षा बैठक में डॉ राज सिंह ठाकुर, यशवंत वर्मा, प्रेम नारायण तिवारी, राजेश अग्रहरि, वन श्री कुवैती, राजेश नरेंद्र सिंह, अभिराज दुबे सहित अन्य जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी रही।

विकास, सुशासन और जनकल्याण के संकल्प को नई गति!



मुख्यमंत्री आदरणीय डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज की कैबिनेट ने डाटा सेंटर विस्तार, सिंचाई परियोजनाओं, 'नमो हरित-नगर योजना', मुख्यमंत्री स्कूटी

योजना, स्वास्थ्य सेवाओं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने वाले अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। विकसित मध्यप्रदेश के संकल्प को निरंतर नई ऊर्जा मिल रही है।

पदोन्नति की शुरुआत होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कनिष्ठ सेवा संघ ने किया स्वागत और माना आभार

राजेश धाकड़

इंदौर संभाग के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कनिष्ठ सेवा संघ द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया पुनः प्रारंभ किए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ होने से अधिकारी एवं कर्मचारियों को उनकी योग्यता और अनुभव के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, कार्यकुशलता में सुधार होगा तथा प्रशासनिक व्यवस्था



भी अधिक प्रभावी बनेगी। संघ ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि राज्य सरकार का यह निर्णय अधिकारियों और

कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक कदम है। इस अवसर पर संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

भीम आर्मी की नव नियुक्त संभाग आईटी सेल प्रभारी नेहा पहारिया का भव्य स्वागत

भिण्ड। भीम आर्मी भारत एकता मिशन की नव नियुक्त ग्वालियर संभाग आईटी सेल प्रभारी नेहा पहारिया का उनके निज निवास पर कार्यकर्ताओं एवं समाजजनों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पुष्पगुच्छ, मालाएं एवं साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया और नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी गईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चंबल संभाग संयोजक देशराज धारिया ने कहा कि ग्वालियर और चंबल दोनों ही संगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण संभाग हैं। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इस बात का संकेत है कि भीम आर्मी निरंतर मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि संगठन बहुजन समाज के महापुरुषों के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति के सुख-दुख में साथ खड़े रहने के लिए प्रतिबद्ध है। नव नियुक्त संभाग आईटी सेल प्रभारी



नेहा पहारिया ने संगठन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करेंगी। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता संगठन को मजबूत करना, आईटी सेल को सक्रिय बनाना तथा महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना होगी। उन्होंने कहा कि वह बहुजन समाज और महापुरुषों के मिशन के लिए पूरी तरह समर्पित हैं तथा संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता और समाज के जरूरतमंद लोगों के साथ हर समय खड़ी रहेंगी। स्वागत समारोह में सुनीता दोहरे, विनय कर्नेरिया, स्मार्टी विवेक, रविन्द्र जाटव, जीतू दोहरे, उदयवीर, कुलदीप, मनीष दोहरे, वंदना, कामिनी, पूजा, नम्रता, ज्योति दोहरे, संगीता, जितेंद्र दोहरे, अभिराज, शिवन्या सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

महापौर, निगमाध्यक्ष एवं जनप्रतिनिधियों ने झिंझरी तालाब के पास रोपे बरगद, कदंब सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे

नवल किशोर

कटनी। पर्यावरण संरक्षण एवं हरित शहर के संकल्प को साकार करने की दिशा में नगर निगम कटनी द्वारा मंगलवार को महाराणा प्रताप वार्ड अंतर्गत झिंझरी तालाब के आसपास पौधरोपण अभियान संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न प्रजातियों के छायादार एवं पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों का रोपण कर हरित वातावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया गया इस अवसर पर महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी, नगर निगम अध्यक्ष श्री मनीष पाठक तथा क्षेत्रीय पार्षद एवं एमआईसी सदस्य तुलसा गुलाब बेन सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने बरगद, कदंब सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया। जनप्रतिनिधियों ने नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण संतुलन ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का भी



आधार हैं। प्रत्येक नागरिक को पौधरोपण के साथ-साथ उसकी नियमित देखभाल का दायित्व भी निभाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान एमआईसी सदस्य डॉ. रमेश सोनी एवं सुभाष साहू, पार्षद शशिकांत तिवारी, समाजसेवी राजू शर्मा, उपयंत्री मोना करेरा सहित नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्थानीय नागरिकों ने भी पौधरोपण कर धरा को हरा भरा बनाने हेतु अपने दायित्वों का निर्वहन किया।

निगम प्रशासन ने बताया कि शहर में हरित क्षेत्र के विस्तार एवं जल स्रोतों के आसपास प्राकृतिक वातावरण को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आगामी समय में नगर के विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण अभियान निरंतर संचालित किया जाएगा। झिंझरी तालाब परिसर में लगाए गए पौधे भविष्य में क्षेत्र की हरियाली बढ़ाने के साथ-साथ जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को भी मजबूती प्रदान करेंगे।

देवबंद में सरकारी जमीन पर कार्रवाई अवैध कब्जे के आरोपों में मदरसे, मस्जिद और मजारों को नोटिस

सहारनपुर। में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए मदरसों, मस्जिदों और मजारों से जुड़े 11 मामलों में नोटिस जारी किए हैं। संबंधित पक्षों को 13 जुलाई तक अपना जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। प्रशासन के अनुसार, जांच में कुछ धार्मिक स्थलों और संस्थानों के सरकारी भूमि पर होने की आशंका सामने आने के बाद राजस्व अभिलेखों की समीक्षा की गई। इसके आधार पर कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही संबंधित मामलों में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं।



अधिकारियों का कहना है

सभी मामलों की सुनवाई राजस्व और न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप की जाएगी। यदि जांच में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा सिद्ध होता है, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। यह कार्रवाई किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण के मामलों की जांच का हिस्सा है। अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

टीबी मुक्त भारत ऐप से टीबी उन्मूलन को मिलेगा बल

कलेक्टर आशीष तिवारी ने दिए व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश, जनभागीदारी से अभियान को मिलेगी गति

नवल किशोर

कटनी। भारत को टीबी मुक्त बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को जन-जन तक पहुंचाने एवं टीबी उन्मूलन की दिशा में डिजिटल भागीदारी को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित “टीबी मुक्त भारत (ई-संगिनी) ऐप” विकसित किया गया है। यह ऐप आम नागरिकों, मरीजों, स्वयंसेवकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को एक साझा डिजिटल मंच पर जोड़ते हुए टीबी से जुड़ी जानकारी, सहायता और सेवाओं को सरल एवं सुलभ बनाता है।

इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म से मिलेगी हर जरूरी जानकारी

“टीबी मुक्त भारत” ऐप एक समग्र एवं इंटरएक्टिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से टीबी संबंधी जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ मरीजों की सहायता, निक्षय मित्रों से जुड़ाव तथा उपचार प्रक्रिया की निगरानी भी संभव है। यह ऐप राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं जनभागीदारी आधारित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐप में टीबी के लक्षण, बचाव, जांच एवं



उपचार से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। साथ ही मरीजों को निक्षय मित्रों एवं स्वयंसेवकों से जोड़ने, पोषण किट का डिजिटल रिकॉर्ड रखने, दवा सेवन की निगरानी करने तथा सेवाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं।

कलेक्टर ने दिए अधिकतम डाउनलोड के निर्देश-जिले में इस अभियान को जनआंदोलन का रूप देने के उद्देश्य से कलेक्टर आशीष तिवारी ने ऐप के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को हर नागरिक तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया है।

धर्मस्थलों में पारदर्शिता: समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता

अमित चौहान



भारत विविध आस्थाओं और संस्कृतियों का देश है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च करोड़ों लोगों की श्रद्धा के केंद्र हैं। इन धार्मिक संस्थानों की सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इनके प्रति लोगों का विश्वास बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। आज समय की मांग है कि धार्मिक संस्थानों में प्राप्त होने वाले दान और चढ़ावे के प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। यह व्यवस्था किसी एक धर्म तक सीमित न होकर सभी धर्मों के धार्मिक संस्थानों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। यदि वित्तीय ऑडिट या जांच की व्यवस्था हो, तो उसके नियम सभी के लिए एक जैसे हों। दान और चढ़ावे का अधिकतम लेन-देन डिजिटल माध्यम से किया जाए, जिससे नकद लेन-देन में होने वाली अनियमितताओं और चोरी जैसी घटनाओं पर

रोक लग सके। साथ ही प्रत्येक धार्मिक संस्थान की आय, व्यय और विकास कार्यों का वार्षिक विवरण सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि श्रद्धालु यह जान सकें कि उनके द्वारा दिया गया दान किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया।

इस दिशा में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष नियामक संस्था अथवा मंत्रालय पर भी विचार किया जा सकता है, जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधियों और वित्तीय विशेषज्ञों की समान भागीदारी हो। इसका उद्देश्य धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि वित्तीय

पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करना होना चाहिए। यदि किसी धार्मिक संस्थान को विकास कार्यों के लिए धन आवंटित किया जाता है, तो उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक हो। इसी प्रकार, वहां कार्यरत कर्मचारियों का रिकॉर्ड और प्रशासनिक व्यवस्था भी सुव्यवस्थित हो। इससे श्रद्धालुओं का विश्वास और मजबूत होगा तथा धार्मिक संस्थानों की गरिमा भी बनी रहेगी। लोकतंत्र में सरकारों का दायित्व केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था विकसित करना भी है जो सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करे।

धार्मिक आस्था

का सम्मान करते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना देशहित में एक सकारात्मक कदम हो सकता है। यह विषय राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित और सुशासन के दृष्टिकोण से विचार किए जाने योग्य है। आस्था और पारदर्शिता साथ-साथ चलें, तभी समाज और राष्ट्र दोनों अधिक मजबूत बनेंगे।



गौशाला या मौत का घर? पिपलोदा में गौमाता की दुर्दशा पर जिम्मेदारों की चुप्पी सवालियों के घेरे में

सूर्या परमार

कागजों में सेवा, जमीन पर सजा! आखिर गौशाला का पैसा जा कहाँ रहा है?

शुजालपुर। ग्राम पंचायत पिपलोदा की गौशाला की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वे सिर्फ एक गौशाला की बदहाली नहीं, बल्कि उन दावों पर भी करारा तमाचा हैं जिनमें गौसेवा की बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। गौशाला में चारों ओर गंदगी, कीचड़, गोबर का अंबार और बदहाल व्यवस्था साफ दिखाई दे रही है। सबसे दर्दनाक तस्वीर उस गाय की है, जिसकी मौके पर मौत हो चुकी थी। सवाल यह है कि आखिर यह मौत बीमारी से हुई, भूख से हुई, लापरवाही से हुई या जिम्मेदारों की संवेदनहीनता से? जिस गौशाला को गौमाता के संरक्षण और सेवा का केंद्र होना चाहिए था, वहां की हालत देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो बेजुबान पशु किसी गौशाला में नहीं, बल्कि ऐसी कैद में जीवन काट रहे हों जहाँ न समय पर भोजन की गारंटी है और न ही समुचित देखभाल की। जेल में बंद कैदी को भी समय पर भोजन और स्वास्थ्य सुविधा मिल जाती है, लेकिन यहाँ गौमाता के हिस्से में क्या आया— गंदगी, बदहाली और अंत में मौत? सबसे बड़ा सवाल ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव से है। क्या यही आपकी गौसेवा है? क्या सरकार से गौशाला संचालन के नाम पर मिलने वाली राशि वास्तव में गौमाता पर खर्च होती है, या फिर कागजों में खर्च दिखाकर लीपापोती कर दी जाती है?



यदि रिकॉर्ड में सब कुछ व्यवस्थित है, तो धरातल पर इतनी भयावह स्थिति क्यों दिखाई दे रही है? यह भी बड़ा प्रश्न है कि क्या गौशालाओं की निगरानी के लिए कोई समिति या जिम्मेदार अधिकारी है? यदि है, तो उसने आखिरी बार इस गौशाला का निरीक्षण कब किया? क्या निरीक्षण सिर्फ फाइलों तक सीमित है और वास्तविकता देखने की किसी को फुर्सत नहीं? हर चुनाव में गौमाता के नाम पर राजनीति होती है, वोट मांगे जाते हैं और गौसंरक्षण के बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं।

लेकिन जब गौमाता की जान बचाने की बात आती है तो जिम्मेदारों की संवेदनाएं आखिर कहाँ चली जाती हैं? अब देखना यह है कि ग्राम पंचायत पिपलोदा की इस गौशाला में सामने आई गंभीर अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होगी या फिर यह मामला भी कुछ दिनों की चर्चा के बाद फाइलों में दफन कर दिया जाएगा। यदि समय रहते जवाबदेही तय नहीं हुई, तो गौसंरक्षण के दावे केवल भाषणों तक सीमित रह जाएंगे और बेजुबान गौमाताओं की मौत का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा।

40 हजार करोड़ की संपत्ति पर सिंधिया राजपरिवार का 'महा-समझौता' आज, अदालत में ऑनलाइन होगी औपचारिक प्रक्रिया ग्वालियर के सिंधिया राजपरिवार की करीब 40 हजार करोड़ रुपये मूल्य की पैतृक संपत्ति से जुड़े बहुचर्चित पारिवारिक विवाद में आज महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री तथा उनकी तीनों बुआ, और ऊषा राजे के बीच संपत्ति बंटवारे को लेकर हुए आपसी समझौते की औपचारिक प्रक्रिया आज न्यायालय में पूरी की जाएगी। बताया जा रहा है कि सभी पक्षकार ऑनलाइन माध्यम से अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे। लंबे समय से चल रहे इस पारिवारिक विवाद को आपसी सहमति से समाप्त करने की दिशा में यह अहम कदम माना जा रहा है। समझौते के बाद संपत्ति के बंटवारे और उससे जुड़े अधिकारों को लेकर वर्षों से चली आ रही कानूनी प्रक्रिया समाप्त होने की संभावना है। यह मामला देश के सबसे चर्चित पारिवारिक संपत्ति विवादों में शामिल रहा है और आज होने वाली न्यायिक कार्यवाही पर राजनीतिक तथा सामाजिक हलकों की भी नजर बनी हुई है।

प्रदेश के सम्मान से समझौता क्यों?



जिस मध्य प्रदेश ने सरदार सरोवर परियोजना के लिए अपनी जमीन दी, अपने जंगल दिए, अपने गाँव डुबोए और लाखों लोगों का विस्थापन सहा, उसी प्रदेश के अधिकारों की रक्षा करने के बजाय भाजपा सरकार ने घुटने टेक दिए। प्रदेश सरकार ने पहले गुजरात से 7,669 करोड़ के मुआवजे की मांग की थी, लेकिन अब समझौते के नाम पर उल्टा 550 करोड़ गुजरात को देने पर सहमति जता दी।

माँ नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में है, नदी का अधिकांश प्रवाह भी यहीं है, फिर भी प्रदेश के किसान सिंचाई के लिए तरस रहे हैं, गाँवों में पेयजल का संकट है और नहरों का विस्तार अधूरा है। ऐसे में प्रदेश के हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखने के बजाय समझौते का रास्ता चुन लिया।

मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है—आखिर प्रदेश के अधिकारों से समझौता क्यों किया गया? प्रदेश के हितों की कीमत पर यह फैसला किसके दबाव में लिया गया? मध्य प्रदेश का स्वाभिमान सर्वोपरि है। प्रदेश के अधिकारों और जनता के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

—जयवर्धन सिंह, कांग्रेस विधायक

160 करोड़ के संदिग्ध लेनदेन पर ईडी का शिकंजा: एआईटीसी से जुड़े 5 ठिकानों पर छापेमारी, विमान-हेलीकॉप्टर सौदों की जांच तेज

नई दिल्ली। ने लगभग 160 करोड़ रुपये के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़े मामले में से जुड़े पांच ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच एजेंसी विमान और हेलीकॉप्टर की खरीद, उनके किराये तथा भुगतान से जुड़े वित्तीय लेनदेन की पड़ताल कर रही है। ईडी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद उन्हें कथित तौर पर एआईटीसी से जुड़े उपयोग के लिए किराये पर दिया गया।



प्रथम दृष्टया पूरा वित्तीय लेनदेन संदिग्ध प्रतीत होता है, इसलिए बैंक खातों, अनुबंधों, भुगतान रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों की विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के दौरान ईडी ने कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और वित्तीय अभिलेख अपने कब्जे में लिए हैं। एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि भुगतान का स्रोत क्या था, धन का वास्तविक लाभार्थी कौन था और क्या इस लेनदेन में धन शोधन या अन्य वित्तीय अनियमितताओं के तत्व मौजूद हैं। हालांकि, जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और एजेंसी की ओर से लगाए गए आरोपों की न्यायिक पुष्टि होना बाकी है। संबंधित पक्षों को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने और न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।